शुक्रवार
18 सितम्बर 2026
- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 237
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल
सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94
email: doonvalley_news@yahoo.com
Website: dunvalleymail.com
डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

कोल पावर प्लांट पर घिरी धामी सरकार

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच उत्तराखंड की सियासत में बिजली का मुद्दा गरमाने लगा है। छत्तीसगढ़ स्थित प्रस्तावित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना से 132० मेगावाट बिजली खरीद के 25 वर्षीय करार को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना को समाप्त कर निजी कंपनी से बिजली खरीद का रास्ता तैयार किया गया और निविदा की शर्तों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। दूसरी ओर सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए प्रक्रिया को नियमसम्मत, प्रतिस्पर्धी और राज्य की दीर्घकालिक बिजली जरूरतों को पूरा करने वाला बताया है।

File Photo

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि 132० मेगावाट की बिजली खरीद के लिए जारी निविदा में कुल 86 में से 84 शर्तों में बदलाव किया गया। कांग्रेस का सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में निविदा शर्तों में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इससे किसी विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने की स्थिति बनी। कांग्रेस के मुताबिक वर्ष 2०24 में उत्तराखंड सरकार ने यूजेवीएनएल और टीएचडीसी के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से 132० मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा था। पार्टी का दावा है कि केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2०25 में इस परियोजना को समाप्त कर दिया गया और फरवरी 2०25 में बिजली खरीद के लिए नया टेंडर जारी किया गया।

कांग्रेस का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राज्य की अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बिजली परियोजना विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही थीं, तो उस प्रस्ताव को समाप्त करने के बाद बाहर से बिजली खरीदने का फैसला क्यों किया गया। पार्टी ने टेंडर में पावर प्लांट को उत्तराखंड के बजाय देश में कहीं भी स्थापित किए जाने की अनुमति, एक ही बोलीदाता से पूरी 132० मेगावाट बिजली लेने तथा ट्रांसमिशन लागत से जुड़े प्रावधानों पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन बदलावों का सीधा संबंध छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित परियोजना से है।

उत्तराखंड कैबिनेट ने अगस्त 2०26 में यूपीसीएल को अदाणी पावर से 25 साल तक 132० मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता करने की अनुमति दी थी। प्रस्तावित दर 5.746 रुपये प्रति यूनिट बताई गई है। नियामक आयोग की स्वीकृति की प्रक्रिया भी इस करार का हिस्सा है। सरकार का तर्क है कि इससे राज्य की भविष्य की आधार-भार बिजली जरूरत सुरक्षित होगी और बिजली खरीद की लागत में अनिश्चितता कम होगी। ष्यही दीर्घकालिक करार अब कांग्रेस के राजनीतिक हमले का केंद्र बन गया है। कांग्रेस ने 25 वर्षों में संभावित भुगतान को लेकर भी सवाल उठाए हैं और पूरी निविदा प्रक्रिया के दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि वह सत्ता में आने पर इस करार की समीक्षा करेगी और यदि किसी स्तर पर अनियमितता मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।

◆कांग्रेस ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने और निविदा की शर्तों में हेरफेर का लगाया आरोप
◆सरकार का दावा-दीर्घकालिक बिजली संकट से निपटने के लिए पारदर्शी तरीके से लिया फैसला
◆विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राज्य की राजनीति में चरम पर पहुंची बयानबाजी

कांग्रेस के आरोपों के बीच सरकार ने अपना पक्ष भी सामने रखा है। प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि 132० मेगावाट बिजली खरीद की प्रक्रिया नियमों, तकनीकी आवश्यकताओं और प्रतिस्पर्धी बोली व्यवस्था के तहत आगे बढ़ी है। उनके अनुसार आरएफक्यू चरण में पांच कंपनियां पात्र पाई गई थीं और अंतिम चयन प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किया गया। प्रमुख सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि प्लांट के लिए उत्तराखंड के बाहर स्थान चुनने का विकल्प तकनीकी, पर्यावरणीय और कोयला परिवहन लागत को ध्यान में रखते हुए रखा गया। सरकार का कहना है कि निश्चित शुल्क की सीमा में बदलाव से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और अंतिम दरों का निर्धारण नियामकीय प्रक्रिया के तहत होगा।

सियासी लड़ाई केवल कांग्रेस के आरोपों तक सीमित नहीं है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस शासनकाल में काशीपुर के गैस आधारित बिजली संयंत्रों से जुड़े महंगे बिजली करार का मुद्दा उठाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मौजूदा करार की दर को कांग्रेस शासनकाल के कथित गैस पावर करार की तुलना में कम बताते हुए इसे राज्य की दीर्घकालिक बिजली जरूरत सुरक्षित करने वाला फैसला बताया है। इस तरह बिजली का मुद्दा अब महज ऊर्जा नीति का सवाल नहीं रह गया है। यह आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच आर्थिक फैसलों, सरकारी बनाम निजी क्षेत्र और जनता पर संभावित वित्तीय बोझ के सवालों को लेकर राजनीतिक टकराव का नया मैदान बनता जा रहा है।

इस पूरे विवाद में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जनता के सामने कुछ ठोस सवाल हैं कि निविदा की शर्तों में बड़े पैमाने पर बदलाव क्यों किए गए? सार्वजनिक क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना को समाप्त करने का तकनीकी आधार क्या था? छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदना उत्तराखंड के लिए दीर्घकाल में कितना किफायती होगा? 25 साल के करार

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली ने की आत्महत्या!

हमारे संवाददाता

हरिद्वार/देहरादून। बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में मौत की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भूपतवाला क्षेत्र में स्थित उसकी चाय की दुकान पर उसका शव मिला। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कोली पिछले कुछ समय से हरिद्वार में रह रहा था और वहां चाय की दुकान चला रहा था।

विदित हो कि सुरेंद्र कोली का नाम वर्ष 2006 में सामने आए नोएडा के निठारी कांड के कारण देशभर में चर्चा में आया था। नोएडा के सेक्टर-31 स्थित निठारी में बच्चों और महिलाओं के लापता होने के मामले ने उस समय पूरे देश को झकझोर दिया था। 29 दिसंबर 2006 को डी-5 कोठी के आसपास मानव अवशेष मिलने के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। सुरेंद्र कोली उस समय निठारी स्थित डी-5 कोठी में घरेलू सहायक के रूप में काम करता था। यह कोठी कारोबारी मनिंदर सिंह पंढेर की थी। बाद में निठारी कांड से जुड़े कई मुकदमों में कोली को आरोपी बनाया गया और उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। निठारी कांड में सुरेंद्र कोली को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई मामलों में उसे दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2023 में भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की रिहाई का रास्ता साफ होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड से जुड़े अंतिम लंबित मामले में भी सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव याचिका स्वीकार करते हुए उसे बरी कर दिया था। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कोली पिछले कुछ महीनों से हरिद्वार में रह रहा था और वहां चाय की दुकान चला रहा था। आज सुबह उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में उसकी मौत की सूचना सामने आई। पुलिस के मुताबिक घटना सप्त सरोवर रोड, लालमाता मंदिर के सामने स्थित चाय की दुकान पर हुई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने कहा है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। शव की पहचान सुरेंद्र कोली के रूप में की गई और उसके अल्मोड़ा निवासी स्वजनों को सूचना दी गई है।

दून वैली मेल

संपादकीय

ड्रैगन से दोस्ती का नया दौर

भारत और चीन के रिश्तों में लंबे समय से जमी बर्फ अब कुछ पिघलती दिखाई दे रही है। 12 सितंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने इस संभावना को बल दिया है कि दोनों एशियाई शक्तियां टकराव की जगह संवाद और सहयोग की नई राह तलाश सकती हैं। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने, मौजूदा समझौतों का पालन करने और व्यापार, कारोबार, सांस्कृतिक संपर्क तथा लोगों की आवाजाही बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी-शी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री वास्तव में उस अविश्वास को खत्म कर सकती है, जिसने 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंधों को गहरे संकट में डाल दिया था? इस सवाल का जवाब फिलहाल जल्दबाजी में देना ठीक नहीं होगा। कूटनीति में हाथ मिलाना आसान है, लेकिन भरोसा कायम करना कठिन। भारत और चीन के बीच संबंध केवल दो नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर नहीं हैं। इनके केंद्र में करीब 3,800 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तैनाती, व्यापार असंतुलन, अरुणाचल प्रदेश को लेकर मतभेद और क्षेत्रीय भू-राजनीति जैसे जटिल मुद्दे हैं। फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की सीमा वार्ता के 25वें दौर में दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा सीमा प्रश्न के उचित, तर्कसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। यानी मोदी-शी मुलाकात कोई अचानक पैदा हुआ घटनाक्रम नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से चल रही सावधानीपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रिया की अगली कड़ी है। भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि सीमा पर शांति और स्थिरता व्यापक संबंधों के विकास की बुनियादी शर्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात में भी इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को सीमा संबंधी मौजूदा समझौतों और सहमतियों का पालन करना चाहिए। साथ ही दोनों नेताओं ने सीमा प्रश्न के निष्पक्ष, तर्कसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता जताई। यही वह बिंदु है जहां दोनों देशों की दोस्ती की असली परीक्षा होगी। आर्थिक संबंध सुधरें, उड़ानें बढ़ें, कारोबार बढ़े और सांस्कृतिक संपर्क मजबूत हों, यह सब स्वागतयोग्य है। मगर सीमा पर भरोसा मजबूत हुए बिना संबंधों की सामान्य स्थिति अधूरी ही रहेगी। 2024 के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव कम हुआ और 2025-26 में राजनीतिक तथा आर्थिक संपर्क भी बढ़े हैं। प्रत्यक्ष उड़ान सेवाएं बहाल हुई हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर शुरू हुई है। भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों के हित एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2025 में द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, लेकिन इसके साथ भारत का व्यापार घाटा भी बहुत बड़ा है। चीन भारत के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक और विनिर्माण आयात का स्रोत बना हुआ है। इसलिए नई दिल्ली के लिए चीन से संबंध सुधारने का अर्थ केवल राजनीतिक सद्भाव नहीं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, विनिर्माण, तकनीक और बाजार पहुंच जैसे व्यावहारिक मुद्दों को भी साधना है। दूसरी ओर भारत चाहता है कि व्यापार संबंध अधिक संतुलित हों और भारतीय उत्पादों के लिए चीनी बाजार में बेहतर तथा पूर्वानुमेय पहुंच मिले। दोनों नेताओं ने हालिया वार्ता में व्यापार असंतुलन और आपूर्ति शृंखला से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मोदी और शी की मुलाकातों में व्यक्तिगत संवाद और राजनीतिक समझ का अपना महत्व है। दोनों नेताओं के बीच पिछले दो वर्षों में कई उच्चस्तरीय संपर्क हुए हैं और संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। चीनी पक्ष ने भी दोनों देशों को साझेदार के रूप में देखने पर जोर दिया है। लेकिन भारत-चीन संबंधों का भविष्य केवल मोदी और शी की केमिस्ट्री से तय नहीं होगा। यह भरोसे के संस्थागत तंत्र, सीमा पर स्थायी शांति, सैन्य तनाव कम करने के उपायों, व्यापार संतुलन और एक-दूसरे की रणनीतिक चिंताओं के सम्मान से तय होगा। भारत को न तो चीन के साथ स्थायी टकराव को अपनी नियति मानना चाहिए और न ही महज कूटनीतिक मुस्कान को स्थायी दोस्ती का प्रमाण। चीन के साथ संबंधों में सहयोग और सावधानी दोनों साथ चलने होंगे। दुनिया इस समय तेजी से बदल रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखलाओं, पश्चिम एशिया के संघर्षों और बदलती वैश्विक शक्ति-समीकरणों के बीच भारत और चीन दोनों के सामने अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने की चुनौती है। ऐसे समय में दुनिया की दो बड़ी आबादी वाले देशों के बीच संवाद का रास्ता खुलना केवल द्विपक्षीय हित में नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए मोदी-शी मुलाकात को दोस्ती की अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि भरोसा बहाल करने की नई शुरुआत के रूप में देखना अधिक यथार्थवादी होगा। ड्रैगन के साथ रिश्तों में भारत को अपनी आंखें खुली रखकर आगे बढ़ना होगा। सीमा पर शांति, आर्थिक हितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता किए बिना सहयोग के दरवाजे खोलना ही व्यावहारिक कूटनीति है। यदि संवाद जमीन पर भी सकारात्मक परिणाम देने लगे, तो मोदी और शी की मुलाकात वास्तव में भारत-चीन संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकती है। लेकिन इसका फैसला हाथ मिलाने की तस्वीर नहीं, सीमा पर शांति और व्यवहार में बदलाव करेगा।

सेवा संकल्प के बहाने भाजपा की चुनावी तैयारी

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में 2०27 के विधानसभा चुनाव की तारीख भले अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों की गतिविधियां लगातार चुनावी रंग ले रही हैं। इसी क्रम में भाजपा का सेवा संकल्प अभियान महज सेवा कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं, बल्कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और संगठन की जमीनी सक्रियता परखने का बड़ा अवसर बनकर सामने आया है। अभियान के तहत 11 प्रमुख कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और इन्हें जिलों से लेकर मंडल स्तर तक ले जाने की तैयारी है। भाजपा की घोषित रणनीति में सेवा, जनभागीदारी, संवाद और नवाचार को केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार अभियान के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से हुए बदलाव तथा लाभार्थियों की कहानियों को जनता के सामने रखा जाएगा। सेवा सेतु जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और शिविरों के जरिए संवाद करने की भी योजना है।

यहीं से इस अभियान का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। चुनावी वर्ष में किसी भी दल के लिए जनता से सीधा संपर्क केवल संगठनात्मक गतिविधि नहीं होता। वह यह समझने का माध्यम भी बनता है कि सरकार की योजनाओं को लेकर जमीन पर क्या प्रतिक्रिया है, किन वर्गों तक लाभ पहुंचा है और किन मुद्दों पर लोगों की शिकायतें बरकरार हैं। भाजपा के सामने इस समय एक तरफ सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच स्थापित करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ संगठन को चुनावी मोड में सक्रिय बनाए रखने की जरूरत है। पार्टी पहले ही बूथ सशक्तीकरण, शक्ति केंद्र बैठकों और घर-घर संपर्क जैसे कार्यक्रमों के जरिए संगठन को अंतिम छोर तक सक्रिय करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है।

ऐसे में सेवा संकल्प अभियान इन गतिविधियों को व्यापक जनसंपर्क से जोड़ने का माध्यम बन सकता है। पार्टी ने अभियान के अलग-अलग कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को भी सौंपी है। इससे सरकार और संगठन के बीच समन्वय की परीक्षा भी होगी। भाजपा का जोर केंद्र और राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने पर है। आशीर्वाद का दीया, नमो सेवा गाथा, कहानी बदलाव की, सेवा मेरा योगदान और सेवा सेतु जैसे कार्यक्रम इसी उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

◆चुनाव की तारीखों से पहले ही जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और संगठन की ताकत परखने की कवायद
◆ज़िले से लेकर मंडल स्तर तक सेवा सेतु और बहुउद्देशीय शिविरों के जरिए जनता के बीच पहुंचेगी पार्टी
◆भाजपा के पास जनता की नब्ज टटोलने, उपलब्धियां गिनाने और संगठन को बूथ तक कसने का मौका

लेकिन राजनीतिक रूप से असली सवाल यह होगा कि क्या योजनाओं का लाभ पाने वाला वर्ग उसी अनुपात में सरकार के पक्ष में राजनीतिक समर्थन भी व्यक्त करता है? यह स्वत: मान लेना उचित नहीं होगा। लाभार्थी की संतुष्टि कई मुद्दों में से एक हो सकती है। रोजगार, महंगाई, पलायन, स्थानीय विकास, भू-कानून, मूल निवास और सरकारी भर्ती जैसे सवाल भी मतदाताओं के राजनीतिक रुख को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि सेवा संकल्प अभियान भाजपा के लिए केवल उपलब्धियां बताने का मंच नहीं, बल्कि फीडबैक लेने की जमीन भी बन सकता है। भाजपा के इस अभियान ने कांग्रेस के सामने भी राजनीतिक चुनौती खड़ी की है। यदि भाजपा घर-घर जाकर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार करती है तो कांग्रेस को उसी जनता के बीच सरकार के दावों की पड़ताल और अपने मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखने की जरूरत होगी।

कांग्रेस के लिए रोजगार, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं, पलायन, कानून-व्यवस्था और विकास के सवाल पहले से राजनीतिक मुद्दे हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में मुकाबला केवल भाषणों और प्रेस वार्ताओं तक सीमित रहने के बजाय सरकार ने क्या किया बनाम जनता को क्या मिला के सवाल पर केंद्रित हो सकता है। सेवा संकल्प अभियान की सफलता का एक पैमाना यह भी होगा कि भाजपा का संगठन कितनी प्रभावी ढंग से इसे बूथ स्तर तक पहुंचाता है। पार्टी ने पहले ही चुनावी तैयारियों को बूथ और

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

सैन्य बहुल राज्य का सियासी गणित

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में 2०27 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अग्निवीर योजना एक बार फिर सियासी विमर्श के केंद्र में आती दिख रही है। कांग्रेस लगातार अग्निपथ योजना को युवाओं के भविष्य और रोजगार से जोड़कर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस पर युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि अग्निवीरों के लिए सेवा के बाद रोजगार और करियर का रोडमैप स्पष्ट है और बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा आवेदन किया जाना योजना में उनकी रुचि को दर्शाता है।

उत्तराखंड में सैन्य सेवा का सामाजिक और भावनात्मक महत्व लंबे समय से रहा है। बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती को करियर के साथ-साथ गौरव और सेवा का अवसर मानते हैं। ऐसे में अग्निपथ योजना का मुद्दा सीधे युवाओं और पूर्व सैनिक परिवारों से जुड़ता है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए यह वर्ग महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह है। यही कारण है कि अग्निवीर योजना अब केवल रक्षा भर्ती की नीति नहीं, बल्कि युवा रोजगार और भविष्य से जुड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। भाजपा ने अग्निपथ योजना के पक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक तर्क बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों को बनाया है। पार्टी का कहना है कि 54 लाख आवेदन इस बात का संकेत हैं कि देश के युवाओं में सेना में भर्ती होने को लेकर उत्साह और रुचि बनी हुई है।

भाजपा के मुताबिक यदि युवा योजना को पूरी तरह अस्वीकार करते, तो इतनी बड़ी संख्या में आवेदन नहीं आते। पार्टी इसे कांग्रेस के उस नैरेटिव का जवाब मान रही है जिसमें अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए नुकसानदेह बताया जाता है। हालांकि आवेदन की संख्या को योजना के प्रति युवाओं की पूर्ण संतुष्टि का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। आवेदन यह जरूर बताते हैं कि सेना में भर्ती के प्रति आकर्षण कायम है, जबकि योजना के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के रोजगार और करियर के आंकड़ों से होगा। कांग्रेस का मुख्य राजनीतिक हमला अग्निवीर की चार वर्ष की सेवा अवधि को लेकर रहा है। पार्टी का तर्क है कि सेना में नियमित भर्ती की जगह सीमित अवधि की सेवा व्यवस्था से युवाओं के सामने चार साल बाद करियर को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है।

◆पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों के वोटों को साधने के लिए चुनाव से पहले राजनीतिक बिसात बिछना शुरू
◆अग्निवीर पर सियासी संग्राम, भाजपा ने कांग्रेस को घेरा, 54 लाख आवेदनों को बनाया हथियार
◆सत्तारुढ़ दल का दावा-योजना के तहत आए रिकार्ड आवेदनों ने साबित किया युवाओं का भरोसा

विपक्ष इस मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़कर युवाओं के बीच ले जाने की कोशिश करता रहा है। कांग्रेस के लिए अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की रोजगार नीति पर सवाल उठाने का माध्यम भी बन रही है। भाजपा का पलटवार है कि कांग्रेस युवाओं के सामने उपलब्ध अवसरों को नजरअंदाज कर केवल भ्रम का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। अग्निपथ योजना पर भाजपा का बचाव केवल योजना के प्रावधानों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट है कि सरकार सेना को युवा शक्ति से जोड़ रही है और अग्निवीरों को सेवा के बाद भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल/राइफलमैन भर्ती में 1० प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। कई राज्यों ने भी पुलिस और अन्य सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए अवसर या प्राथमिकता संबंधी फैसले लिए हैं। भाजपा इन्हीं प्रावधानों को अग्निवीरों के लिए तैयार किए गए रोडमैप के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। उत्तराखंड के लिए अग्निवीर योजना का राजनीतिक महत्व दूसरे राज्यों की तुलना में अलग है। पहाड़ों में सेना की नौकरी को लेकर पीढ़ियों पुरानी परंपरा रही है। सेना में भर्ती यहां रोजगार के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा और देशसेवा से भी जुड़ी रही है।

इसलिए कांग्रेस अगर अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य का सवाल बनाती है तो भाजपा के लिए जरूरी होगा कि वह प्रदेश के युवाओं के बीच योजना के बाद

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

झूला पुल निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस ने निकाली जनजागरण यात्रा

हरिद्वार (आरएनएस)। रवासन नदी पर झूला पुल निर्माण की मांग को लेकर हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने ग्रामीणों के साथ जनजागरण यात्रा निकाली। आर्यनगर गोठ से मंगोलपुरा तिराहे तक निकाली गई यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द पुल निर्माण शुरू कराने की मांग उठाई गई। विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि वर्ष 2०21-22 में झूला पुल के लिए प्रथम किस्त जारी कर दी गई थी, लेकिन चार वर्ष बाद भी सरकार वन विभाग और अन्य आपत्तियों का निस्तारण नहीं करा पाई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में वह कई बार झूला पुल का मुद्दा उठा चुकी हैं। यदि सरकार समय रहते पुल का निर्माण करा देती तो आज जानमाल की अपूरणीय क्षति नहीं होती। इसके लिए उन्होंने भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ता भी अपनी ही सरकार से पुल निर्माण की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, जो विचारणीय विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वह ग्रामीणों के साथ अनशन शुरू करने को बाध्य होंगी। यात्रा में कांग्रेस नेता गुरजीत लहरी, टीकाराम सैनी, शैलेंद्र पाठक, खेम सिंह, चंद्रप्रकाश इंशा, विनोद अधिकारी, अनीस अहमद, सलेक चंद, जग्गी सिंह, जगत पटवाल, विजेंद्र कुणार, महेश्वरी देवी, शकुंतला, विमला देवी, चंद्रवती देवी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर निगम और व्यापारियों में बनी सहमति

रुड़की(आरएनएस। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर नगर निगम सभागार में मुख्य नगर आयुक्त और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर निगम को सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि व्यापारी भी सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने में निगम का साथ देंगे। साथ ही पदाधिकारियों ने मांग की कि कार्रवाई के दौरान किसी भी व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए। व्यापारियों ने कहा कि नियमों के पालन में वे नगर निगम का सहयोग करेंगे और अन्य व्यापारियों को भी जागरूक करेंगे। नगर निगम अधिकारियों ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और रोक के प्रावधानों की जानकारी दी।बैठक में निगम और व्यापारियों के बीच समन्वय बनाकर अभियान चलाने पर जोर दिया गया। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि व्यापारियों के सहयोग से सिंगल यूज प्लास्टिक को रोका जाएगा। बैठक में व्यापार मंडल प्रदेश संगठन मंत्री राम गोपाल कंसल, नवीन गुलाटी, नगर अध्यक्ष धीर सिंह, आईआईटी के प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा आदि मौजूद रहे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग में विद्यार्थियों ने दिखाई वैज्ञानिक प्रतिभा

अल्मोड़ा(आरएनएस)। राजकीय इंटर कॉलेज मनान में विकासखंड ताकुला की द्वितीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों से 46 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक विज्ञान समन्वयक डॉ. संजय पांडे ने की, जबकि संचालन ब्लॉक विज्ञान सह समन्वयक अंकित जोशी ने किया। विभिन्न चरणों में आयोजित विज्ञान क्विज में विद्यार्थियों ने त्वरित सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विषयगत ज्ञान का परिचय दिया। सीनियर वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज मनान की कामाक्षी ने प्रथम, राजकीय इंटर कॉलेज सोमेश्वर की उदिता जोशी ने द्वितीय तथा राजकीय इंटर कॉलेज गणानाथ के लव कांडपाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चनौदा की चंचल भाकुनी प्रथम, रा. उ. मा. वि. लोध की आरुषि द्वितीय तथा श्री राम विद्या मंदिर डोटियालगांव के प्रत्यूष सिंह तृतीय रहे। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विज्ञान संबंधी प्रश्नों और गतिविधियों के माध्यम से अपनी वैज्ञानिक सोच, तार्किक क्षमता, जिज्ञासा एवं त्वरित निर्णय क्षमता का प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी गईं। आयोजकों ने प्रतिभागी विद्यार्थियों, मार्गदर्शक शिक्षकों एवं सहयोगी विद्यालयों का आभार जताते हुए भविष्य में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करने की बात कही।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

शिवालिक नगर क्षेत्र में कुंभ की तैयारियों का मेलाधिकारी ने लिया जायजा

हरिद्वार(आरएनएस। कुंभ मेला-2०27 की तैयारियों को गति देने के लिए मेला प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र के साथ ही आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी विभिन्न व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने शिवालिक नगर क्षेत्र का भ्रमण कर कुंभ मेला से संबंधित विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का स्थलीय जायजा लिया।भ्रमण के दौरान मेलाधिकारी ने शिवालिक नगर क्षेत्र में कुंभ मेला की तैयारियों के तहत चल रहे पुल एवं सड़क निर्माण सहित अन्य योजनाओं की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने चौराहों के सुधार, पार्किंग व्यवस्था एवं सौंदर्यीकरण तथा जन-सुविधाओं से संबंधित कार्यों और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। मेलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों में तत्परता से कार्रवाई करते हुए बेहतर समन्वय के साथ कार्यों को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

मेलाधिकारी ने कहा कि कुंभ मेला-2०27 के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेला क्षेत्र के साथ श्रद्धालुओं की आवाजाही से जुड़े प्रमुख मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में भी आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण एवं विकास कार्यों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम आवागमन और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए।

इस दौरान मेलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद शिवालिकनगर के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा तथा क्षेत्र के अन्य स्थानीय लोगों के साथ कुंभ की तैयारियों को लेकर विचार-विमर्श किया। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा कुंभ के दौरान जन-सुविधाओं को और बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव लिए। मेलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय लोगों के सुझाव व्यवस्थाओं को अधिक उपयोगी और व्यवहारिक बनाने में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार कार्ययोजना में शामिल करने के निर्देश दिए।

मेलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न विभागों के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखने तथा कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किए जाएं, ताकि आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

इस अवसर पर एचआरडीए के सचिव श्री प्रत्यूष सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता श्री योगेश कुमार, एचआरडीए के उद्यान अधिकारी श्री ए.आर. जोशी सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

19 को रायबरेली-गंगागंज रेलखंड पर छह घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक

रुड़की (आरएनएस)। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल की ओर से जारी सूचना के अनुसार रायबरेली जंक्शन-गंगागंज रेलखंड के बीच 19 सितंबर को छह घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 151 और 152 को बंद करने का कार्य किया जाएगा।

रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक मुरादाबाद मंडल महेश यादव के मुताबिक 19 सितंबर को 13००5 हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस करीब 15० मिनट, 15119 बनारस-देहरादून एक्सप्रेस 15० मिनट और 12355 पटना-जम्मूतवी एक्सप्रेस करीब 5० मिनट नियंत्रित अथवा विलंबित रहेगी। वहीं 13००6 अमृतसर-हावड़ा एक्सप्रेस को 21० मिनट तक नियंत्रित किया जा सकता है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि 19 सितंबर को यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन के समय और परिचालन की अद्यतन स्थिति की जानकारी रेलवे की अधिकृत सूचना सेवाओं या 139 हेल्पलाइन से प्राप्त कर लें।

मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन में अल्मोड़ा के 12 विद्यार्थियों का चयन

अल्मोड़ा(आरएनएस। मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन अभियान के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद के 12 विद्यार्थियों का राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। चयनित विद्यार्थी 18 सितंबर 2०26 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ %कैसा हो मेरे सपनों का उत्तराखंड% विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम में राज्यभर से चयनित 14० विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ संवाद से पहले शासन के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष भी चयनित विद्यार्थियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, वन एवं पर्यावरण, स्वरोजगार, पलायन, लोक निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन तथा महिला एवं बाल विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों के सुझाव सुने जाएंगे। विभागीय अधिकारी उपयोगी एवं व्यावहारिक सुझावों की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन अभियान की शुरुआत 1० अगस्त 2०26 को हुई थी। इसके तहत कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों से राज्य के विकास और भविष्य को लेकर विचार आमंत्रित किए गए थे। अभियान में राज्य के 2,67,744 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने विचार भेजकर सहभागिता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। प्राप्त प्रविष्टियों का विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन करने के बाद 14० श्रेष्ठ विचारों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों के विचारों को शासन की नीति-निर्धारण प्रक्रिया से जोड़ने पर जोर दिया है। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 12 के बाद करियर कोचिंग के लिए अधिकतम दो लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दिए जाने की घोषणा भी की गई है। अभियान का उद्देश्य युवाओं को राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बनाना तथा उनके नवाचारपूर्ण सुझावों को सरकारी योजनाओं एवं नीतियों में उपयोग करना है।

सरकारी जमीनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही भाजपा सरकार :भूपेंद्र सिंह भोज

अल्मोड़ा(आरएनएस)। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों की बहुमूल्य भूमि एवं संपत्तियों को लीज पर देने और पीपीपी मोड के नाम पर निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से प्रदेश की बहुमूल्य सरकारी संपत्तियों को निजी हितों के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी दिखाई दे रही है। भोज ने कहा कि उत्तराखंड की जमीन केवल सरकार की संपत्ति नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की अमानत है। सरकारी विभागों की बेशकीमती जमीनों को लंबे समय के लिए लीज पर देने से पहले सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किन जमीनों को किस व्यक्ति अथवा कंपनी को, कितनी अवधि और किन शर्तों पर दिया जा रहा है। उन्होंने मसूरी स्थित पार्क एस्टेट (हाथीपांव) की लगभग 142 एकड़ भूमि को कथित तौर पर 15 वर्षों की लीज पर दिए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि यदि सरकारी भूमि का बाजार मूल्य हजारों करोड़ रुपये है और उसे कम वार्षिक लीज राशि पर लंबे समय के लिए दिया जा रहा है तो सरकार को पूरी प्रक्रिया और वित्तीय औचित्य सार्वजनिक करना चाहिए। भोज ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के माध्यम से सरकारी जमीनों और संपत्तियों को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि सरकारी जमीनों को लीज पर देने और पीपीपी मोड में सौंपने से संबंधित प्रस्ताव, निविदाएं, लीज की शर्तें, बाजार मूल्य, लीज राशि और लाभार्थी कंपनियों की जानकारी सार्वजनिक की जाए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं अन्य जनहित के कार्यों में उपयोग की जा सकने वाली संपत्तियों को जनहित में इस्तेमाल किया जाए। भोज ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड की जमीन और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की किसी भी कोशिश का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता नहीं बरती गई तो कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के साथ सड़क से सदन तक उठाएगी।

तनाव को कम करने में सहायक है साउंड बाथ थेरेपी, जानिए इसके 5 फायदे

साउंड बाथ थेरेपी एक खास तकनीक है, जो तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद करती है। इसमें अलग-अलग प्रकार की आवाजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके मन और शरीर को सुकून देती हैं। यह तरीका न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि शारीरिक आराम भी देता है। आइए जानते हैं कि साउंड बाथ थेरेपी के क्या-क्या फायदे हैं, ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें।

मन को शांत करने में मददगार : साउंड बाथ थेरेपी में इस्तेमाल होने वाली ध्वनियां आपके मन को स्थिर करती हैं। जब आप इस थेरेपी का अनुभव करते हैं तो बाहरी शोरगुल से दूर होकर एक शांत माहौल में पहुंचते हैं। इससे आपका मन शांत होता है और आप एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह तरीका आपके दिमाग को आराम देता है और चिंता को कम करने में मदद करता है। इससे मन की चिंताएं दूर होने लगती हैं।

अच्छी नींद पाने में सहायक : अगर आपको नींद आने में परेशानी होती है तो साउंड बाथ थेरेपी आपके लिए मददगार हो सकती है। इस थेरेपी के दौरान सुनाई देने वाली आवाजें आपके दिमाग को शांत करती हैं और आपको बेहतर नींद लेने में मदद करती हैं। नियमित रूप से इस थेरेपी का इस्तेमाल करने से आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरती है और आप सुबह ताजगी महसूस करते हैं। इसे करवाने के बाद शरीर आराम की स्थिति में आ जाता है और नींद आ जाती है।

शरीर को आराम देने के लिए सही : साउंड बाथ थेरेपी से न सिर्फ मन को सुकून मिलता है, बल्कि यह शरीर को भी आराम देती है। इसमें सुनाई देने वाली आवाजें आपके शरीर की थकी हुई मांसपेशियों को राहत देती हैं, जिससे उनका तनाव धीरे-धीरे कम होने लगता है। इससे आपका शरीर हल्का और आरामदायक महसूस करता है। यह थेरेपी थकान और तनाव को दूर करने का एक अच्छा तरीका है। इससे दर्द आदि से भी राहत मिल सकती है।

ध्यान के लिए सबसे बढ़िया विकल्प : साउंड बाथ थेरेपी से आपकी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। इस थेरेपी के दौरान आप केवल सुनाई देने वाली आवाजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आपका मन एक जगह पर टिकता है। यह आपकी सोचने और समझने की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। इसके नियमित अभ्यास से आप अपने काम में अधिक ध्यान और फोकस ला सकते हैं। साथ ही इससे मानसिक स्वास्थ्य धीरे-धीरे ठीक होता है।

भावनाओं को संतुलित करने में फायदेमंद : साउंड बाथ थेरेपी आपकी भावनाओं को संतुलित करने में भी मदद कर सकती है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आपके अंदर की नकारात्मक सोच और भावनाएं कम हो जाती हैं। यह थेरेपी आपको सकारात्मक सोचने और बेहतर महसूस करने में मदद करती है। इसे अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल और तनावमुक्त बना सकते हैं।

एक्सरसाइज करने के लिए करें फोम रोलर का इस्तेमाल, जानिए इससे जुड़ी अहम बातें

फोम रोलर एक ऐसा साधन है, जो आपकी एक्सरसाइज को और असरदार बना सकता है। यह मांसपेशियों को आराम देने, शरीर को लचीला बनाने और थकान कम करने में मदद करता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह शरीर को चोटों से बचाने और फिटनेस को बेहतर बनाने में भी सहायक हो सकता है। आइए जानते हैं कि फोम रोलर का उपयोग कैसे किया जा सकता है और यह आपकी दिनचर्या में क्यों जरूरी है।

मांसपेशियों की थकान को करता है दूर : एक्सरसाइज के बाद मांसपेशियों में अक्सर थकान और दर्द महसूस होता है। इसका मुख्य कारण मांसपेशियों में बनने वाला एसिड होता है, जो थकावट बढ़ा सकता है। फोम रोलर का इस्तेमाल करने से मांसपेशियों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है और यह एसिड बाहर निकल जाता है। इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और वे जल्दी ठीक हो जाती हैं। नियमित रूप से करने पर भारी एक्सरसाइज के बाद भी आप बेहतर महसूस करेंगे।

शरीर को लचीला बनाने में मददगार : फोम रोलर का उपयोग करने से शरीर का सख्तपन कम होता है और लचीलापन बढ़ता है। यह खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है, जिनकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं या जो स्ट्रेचिंग में परेशानी महसूस करते हैं। फोम रोलर मांसपेशियों को खींचने और उन्हें आराम देने में मदद करता है। यह आपके शरीर की हलचल को आसान बनाता है और एक्सरसाइज को ज्यादा प्रभावी बनाता है। इसके जरिए शरीर अच्छी तरह मुड़ता है।

चोटों से बचाने में सहायक : फोम रोलर का उपयोग करने से चोट लगने का खतरा कम हो सकता है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर को स्थिरता देता है। अगर आप पहले से किसी चोट से परेशान हैं तो इसका इस्तेमाल करने से मांसपेशियों में आराम मिलेगा और उनकी ताकत फिर से लौटेगी। यह आपको ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी तरीके से एक्सरसाइज करने में मदद करता है। हालांकि, आपको इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

तनाव और थकावट होता है कम : फोम रोलर न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करने में मदद करता है। इसे इस्तेमाल करने से मांसपेशियां आराम करती हैं और शरीर हल्का महसूस होता है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो दिनभर के काम के बाद थकान और तनाव का अनुभव करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आप न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस करेंगे।

काफी कोशिशों के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है?

बहुत से लोग वजन कम करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ को अपना वजन कम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर कौन सी वे बीमारियां हैं जो हमारे शरीर को वजन घटाने से रोकती हैं। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल संतुलन को बाधित करती हैं जिससे वजन कम कर पाना मुश्किल हो जाता है। ये बीमारियां हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म क्रिया को धीमा करके या भूख बढ़ाकर वजन कम होने से रोकती हैं। अगर आपको लगता है कि वजन घटाने के लिए आप कितनी भी कोशिश क्यों न करें, वजन कम नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आप इन बीमारियों का शिकार हो।

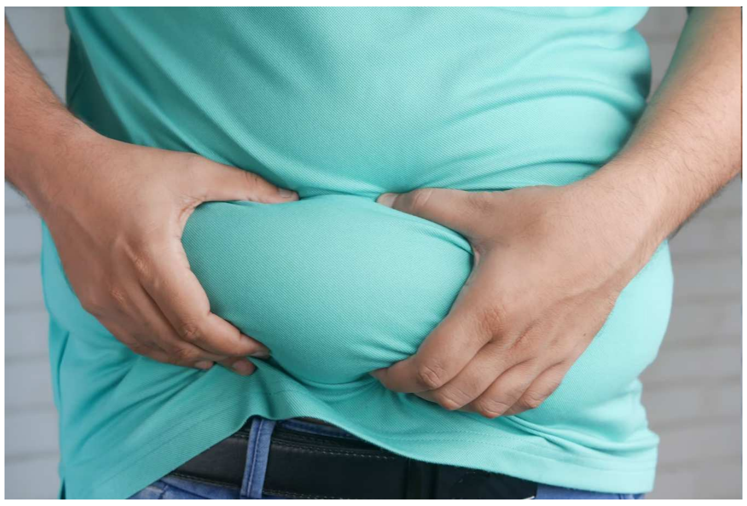

थायरॉयड

थायरॉयड हार्मोन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म बीमारी होता है जिससे भी वजन कम करना कठिन हो जाता है। व्यक्ति चाहकर भी अपना वजन कम नहीं कर पाता। क्योंकि थायरॉयड हार्मोन की अधिक होने से लोगों का मोटापा बढ़ता है। थायरॉयड के संतुलन के बिना शरीर का वजन, चाहे वह कम हो या ज्यादा, नियंत्रित नहीं रह पाता। अत- थायरॉयड की समस्या वजन घटाने में एक बड़ी बाधा बनती है।

पीसीओएस

पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक आम समस्या है जो महिलाओं में देखी जाती है। पीसीओएस वाली महिलाओं के शरीर में इन्सुलिन नामक हार्मोन ज्यादा होता है। इन्सुलिन की वजह से खाने से मिलने वाली कैलोरी जल्दी वसा में बदल जाती है। यानी मोटापा बढ़ने लगता है। इसके अलावा, हार्मोन्स में असंतुलन होने से पीसीओएस में शरीर की सामान्य प्रक्रियाएं भी बिगड़ जाती हैं। इनमें से एक मेटाबॉलिज्म कहलाने वाली प्रक्रिया है। इन सब कारणों से, पीसीओएस वाली महिलाएं डाइट पर कंट्रोल और एक्सरसाइज करने के बाद भी वजन नहीं घटा पातीं।

कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स

कॉर्टिकोस्टेरॉयड शरीर में मौजूद एक प्रकार का हार्मोन होता है, जो स्ट्रेसफुल स्थितियों में अतिरिक्त मात्रा में बनता है। इस हार्मोन की अधिकता से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिनमें से एक है - वजन बढना और फिर वजन कम करने में परेशानी। एक बार जब व्यक्ति मोटा हो जाता है तो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉयड के कारण उसे अपना वजन कम करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि कॉर्टिकोस्टेरॉयड की अधिकता वाले लोग आसानी से वजन नहीं कम कर पाते।

डिप्रेशन

डिप्रेशन के कारण कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है, जबकि कुछ लोग अधिक खाने लगते हैं। जो लोग अधिक खाते हैं, उनमें तेज़ी से वजन बढने लगता है। डिप्रेशन में शरीर में सेरोटोनिन नामक हार्मोन कम हो जाता है, जो भूख और मूड को नियंत्रित करता है।

की बोर्ड काम करते वक्त पर लंच से हो सकता है मोटापा

अक्सर देखा गया है कि लोग की बोर्ड पर काम भी करते रहते है और एक हाथ से नाश्ता भी करते रहते है। परंतु यह ठीक नहीं है।

शोधकर्ताओं के अनुसार डेस्क पर काम करते समय नाश्ता करने से व्यक्ति ज्यादा कर लेता है। जिसका परिणाम मोटापे के रूप में सामने आता है। शोधकर्ताओं ने अपने शोध में पाया कि स्मृति और ध्यान कैसे हमारे भूख को प्रभावित करता है।

अध्ययन के दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के एक समूह को लंच खाने को दिया। लंच में नौ प्रकार के विभिन्न आइटम थे। ये सभी प्रतिभागी लंच करते समय कम्प्यूटर पर एक विशेष गेम खेल रहे थे। जबकि प्रतिभागियों का दूसरा समूह बिना किसी मानसिक कार्य के सिर्फ लंच कर रहा था। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो समूह लंच करते समय कम्प्यूटर गेम खेल रहा था, लंच के बाद उसका भूख पूरी तरह नहीं मिटी थी और आधे घंटे बाद ही उन्होंने फिर से उतना ही लंच खा लिया। यहीं नहीं इस दौरान उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उन्होंने किस क्रम में और कितना आयटम खाया। शोधकर्ताओं ने कहा कि शोध से सिद्ध होता है कि ऐसे लोग भोजन ज्यादा करते हैं जो आगे चलकर मोटापे का रूप लेता है।

शब्द सामर्थ्य -076

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. राजद प्रमुख 6. रखवाला, रक्षा करने वाला 7. दयालु, रहम करने वाला (उ.) 10. युग्म, जोड़ा, एक राशि, एक फिल्म अभिनेता 13. कैदखाना, जेल, हिरासत 15. जानकी, जनकनंदनी 17. व्यर्थ की बात, बकबक 18. नारी, स्त्री, महिला 21. विक्रय करना 22. वाणी, कथन, वादा 24. ताश में दस अंकों वाला पत्ता 25. नगर का, नागरिक, चतुर।

ऊपर से नीचे

1. बेफ्रिक, निश्चिंत, जिसे कोई परवाह न हो 2. मूर्ति 3. दोस्त, प्रेमी 4. कुशल, विशेषज्ञ 5. बगुला 8. झुका हुआ, झुकाया गया, नत 9. इधर-उधर, पास पड़ोस 11. किस्मत, तकदीर, भाग्य 14. बंदर, मर्कट, कपि 16. शक्तिशाली, बलवान 18. संतान, संतति 19. अस्तबल, घुड़साल 20. राजी करना, रूठे हुए को प्रसन्न करना 23. सरिता, नदिया, नद।

1		2			3	4	5	■
	■		■	■	6			■
7			8	■	■	■	■	9
	■	■	10		11	■	12	
13	14			■	15	16	■	
■		■	■	■	17			
18		19	■	20	■		■	■
	■	21			■	22		23
24			■	25			■	

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 75 का हल

मा	म	ला	■	सि	वा	य	■	कि
लि	■	चा	ह	त	■	म	म	ता
क	सू	र	■	म	ग	न	■	ब
■	र	■	■	■	द	■	■	■
क	मा	न	■	पा	र	स	■	स
मी	■	म	जा	ल	■	न	क	ली
ना	दा	न	■	ना	र	द	■	का
■	मि	■	■	■	तौं	■	■	■
सु	नी	ल	■	अ	धी	र	■	जी

अजय देवगन से भिड़ेंगे पुष्पा के विलेन फहाद फासिल!

पुष्पा और पुष्पा 2 जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के विलेन फहाद फासिल ने इन फिल्मों के जरिए देश दुनिया में पहचान बनाई थी. पुष्पा फ्रेंचाइजी में विलेनगिरी से वो हर किसी के दिल पर राज करने लगे थे. हालांकि आपको बता दें कि वो लीड एक्टर के रूप में भी काम करते हैं. अब उनकी एक अपकमिंग फिल्म की नई रिलीज डेट आई है और इसका सामना बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की दृश्यम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म दृश्यम–द कन्क्लूजन से होगा.

फहाद फासिल की आने वाली फिल्म का नाम है डोंट ट्रबल द ट्रबल. मेकर्स ने पहले इस फिल्म को अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान के सामने रिलीज करने का ऐलान किया था. फिल्म के लिए पहले तय रिलीज डेट 11 सितंबर 2०26 थी. हालांकि मेकर्स ने अब इसमें बदलाव कर दिया है.

मेकर्स ने डोंट ट्रबल द ट्रबल की नई रिलीज डेट का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें फहाद के साथ एक छोटी बच्ची भी नजर आ रही है. दोनों सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं. इस चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम सारा पालेकर है जो फिल्म में दिव्या के रोल में नजर आएंगी. जबकि फहाद इसमें सूरी नाम का किरदार निभा रहे हैं. इसका पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, सूरी और दिव्या अपना जादू चलाने और गड़बड़ शुरू करने के लिए तैयार हैं! डोंट ट्रबल द ट्रबल 2 अक्टूबर से सिनेमाघरों में.

अजय देवगन की सफल फ्रेंचाइजी दृश्यम की तीसरी फिल्म दृश्यम–द कन्क्लूजन भी सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को ही रिलीज होगी. अजय देवगन जैसे बड़े स्टार और सफल फ्रेंचाइजी की फिल्म होने के चलते दृश्यम 3 तगड़ी कमाई करेगी. ऐसे में फहाद की फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर टिकना मुश्किल होगा.

फैंटेसी कॉमेडी–ड्रामा फिल्म को दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजामौली ने प्रजेंट किया है. वहीं इसके प्रोड्यसूर हैं राजामौली के बेटे एसएस कार्तिकेय, प्रसाद देविनैनी और शोभू यारलागड्डा. जबकि फिल्म का डायरेक्शन किया है शशांक येलेटी ने.

मलयालम फिल्म हाफ से जुड़े फरहान अख्तर!

अभिनेता–निर्माता फरहान अख्तर ने अपने फैंस को नया तोहफा देने की तैयारी कर ली है। इस बार वो मलयालम वैम्पायर थ्रिलर फिल्म हाफ से जुड़े हैं, जिसका ऐलान उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर किया। उन्होंने बताया कि वह और रितेश सिधवानी, अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट और एए फिल्म्स के सहयोग से फिल्म हाफ को पूरे उत्तर भारत में हिंदी भाषा में प्रस्तुत और रिलीज करेंगे। सितंबर, 2०26 में इसका प्रीमियर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मिडनाइट मैडनेस में होगा।

हाफ एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज होने वाली पहली मलयालम फिल्म होगी। इसका निर्देशन समजद ने किया है, जिन्हें मलायलम फिल्म गोलम (2०24) के लिए जाना जाता है।

कहानी वैम्पायर (पिशाच) लोककथाओं पर आधारित हिंसक शिकार, बदले और खून–खराबा के इर्द–गिर्द घूमती है।

फिल्म में रंजीत सजीव, ऐश्वर्या राज, अब्बास और अमला पॉल को मुख्य किरदार निभाते देखा जाएगा।

टोरंटो महोत्सव में प्रदर्शित होने के बाद ये फिल्म भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी।

विद्युत जामवाल की फिल्म स्ट्रीट फाइटर का ट्रेलर रिलीज, हॉलीवुड में मचाएंगे तहलका

विद्युत जामवाल ने बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक अपने दमदार अभिनय से वाहवाही लूटी है। अब वह हॉलीवुड सिनेमा के जरिए वैश्विक पहचान बनाने के लिए तैयार हैं और उनकी डेब्यू फिल्म स्ट्रीट फाइटर का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। पैरामाउंट पिक्चर्स इंडिया द्वारा रिलीज फिल्म का यह फाइनल ट्रेलर है, जबकि पहला ट्रेलर अप्रैल में आया था। इसका निर्देशन किताओ सकुराई ने किया है, जिसमें नोआ सेंटिनियो, जेसन मोमोआ, रोमन रेंज और एंड्रयू कोजी भी हैं।

स्ट्रीट फाइटर कैपकॉम के मशहूर वीडियो गेम पर आधारित है, जिसकी कहानी 1993 के दौर में सेट है। विद्युत इसमें योग गुरु धल्सिम बने हैं।

कहानी 2 बिछड़े मार्शल आर्ट्स दोस्तों, रयू (एंड्रयू) और केन (नोआ) के इर्द–गिर्द घूमती है, जिन्हें एक खतरनाक वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट में शामिल किया जाता है। 4यहां उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकों से भिड़ना पड़ता है।

ट्रेलर में दमदार एक्शन सीक्वेंस की झलक देखने को मिलती है। फिल्म 16 अक्टूबर, 2०26 को रिलीज होगी।

फिल्म की स्टारकास्ट फिल्म का डायरेक्शन किताओ सकुराई ने किया है। इसमें नोआ सेंटिनियो (केन मास्टर्स), एंड्रयू कोजी (रयू), कैलिना लियांग (चुन–ली), जो अनोआई (अकुमा), डेविड डास्टमलचियन (एम. बाइसन), कोडी रोड्स (गाइल), एंड्रयू शुल्ज (डैन हिबिकी), एरिक आंद्रे (डॉन सॉवेज), विद्युत जामवाल (धाल्सिम), ऑरविल पेक (वेगा), ओलिवियर रिच्टर्स (जैंगिफ), हिरोकी गोटो (ई. होंडा), रैना वल्लैंडिंघम (जुली), अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की (जो), कर्टिस 5० सेंट' जैक्सन (बालरॉग) और जेसन मोमोआ (ब्लांका) शामिल हैं।

डोंट बी शाय को लेकर नर्वस महसूस कर रहीं आलिया भट्ट

अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी प्रोड्यूस आगामी फिल्म डोंट बी शाई को लेकर सुर्खियों में चल रही हैं। अभिनेत्री ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान बताया कि वह फिल्म के साथ चार नए एक्टर्स और एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने को लेकर ज्यादा नर्वस हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान आलिया से पूछा गया था कि क्या उन्हें कभी लगा कि उन्हें भी इस फिल्म में एक्टिंग करनी चाहिए थी, तो इस पर उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस फिल्म में एक्टिंग करनी चाहिए थी।

आलिया ने फिल्म को लेकर उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने से उन्हें एक अलग तरह की खुशी मिली है, क्योंकि वह शुरू से ही इसकी कहानी और इसकी दुनिया बनाने में शामिल रही हैं। उन्होंने कहा, 14 साल पहले मैंने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से एक एक्टर के तौर पर अपना डेब्यू किया था और अब इतने सालों बाद मैं चार नए एक्टर्स और एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रही हूं और मैं अभी उनसे कहीं ज्यादा नर्वस हूं।

क्योंकि, आपके सवाल का जवाब दूं तो, मुझे एक एक्टर होना और कैमरे के सामने रहना पसंद है, लेकिन एक प्रोड्यूसर होने का एक अलग ही तरह का सुकून है। एक्ट्रेस ने आगे कहा- जब फिल्म की निर्देशक श्रीति मुखर्जी हमारे पास इस मूवी बनाने का आइडिया लेकर आईं, तो हमने ही कहा कि चलो इसे साथ में करते हैं और फिर हम इसे अपने प्यारे पार्टनर्स के पास ले गए।

यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और हर कोई इससे जुड़ पाएगा। श्रीति मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म डोंट बी शाय 2० साल की लड़की श्यामिली शाइ दास की कहानी है, जो मानती है कि उसने ज़िंदगी को समझ लिया है, लेकिन वह देखती है कि उसकी सोची–समझी जिंदगी एक अचानक मोड़ ले लेती है, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है।

इसमें आरुषि बजाज, पीयूष खाती, बियांका अरोड़ा और अंश दुग्गल जैसे नए चेहरे मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ कुणाल रॉय कपूर और नेहा धूपिया भी नजर आएंगे। 25 सितंबर 2०26 को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है।

आर्मी मेजर बनने के लिए लेनी पड़ी खास ट्रेनिंग:अशिमता बख्शी

अशिमता बख्शी इन दिनों टीवी शो 1०8 बेस हॉस्पिटल – उरी में आर्मी मेजर और नर्स अनीता सोलंकी के किरदार में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने बताया कि शो का कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से वह शो के लिए मना नहीं कर पाईं। उन्होंने बताया, इस शो में मैं एक नर्स का किरदार निभा रही हूं, जो सेना में मेजर भी है। इस शो के मेकर्स के साथ मैंने पहले भी काम किया है। वह इस किरदार के लिए कास्टिंग कर रहे थे और मुझे लगता है कि यह आखिरी रोल था जिसे उन्हें फाइनल करना था। उन्होंने मुझे इसके लिए बुलाया और किरदार के बारे में बताया। अशिमता बख्शी ने बताया कि शो के साथ उनके किरदार की भी कहानी बढ़ेगी। उन्होंने बताया, मेरा किरदार बहुत ही अच्छा है और यह कहानी के साथ–साथ आगे बढ़ेगा। सबसे खास बात यह है कि शो डेली सोप से बिल्कुल अलग है। इसी कॉन्सेप्ट ने मुझे उत्साहित किया और मैंने इसे करने का फैसला लिया।

अभिनेत्री ने आगे बातचीत में यह भी बताया कि उन्होंने इस रोल के लिए क्या तैयारी की थी। उन्होंने कहा, जब आप किसी आर्मी नर्स का किरदार निभा रही हो और वो मेजर भी है, तो सही बॉडी लैंग्वेज होना जरूरी है। रीडिंग सेशन के दौरान हमें बताया भी गया था कि पोस्चर और स्टांस कैसा होना चाहिए और आर्मी ऑफिसर के तौर पर हमें एक–दूसरे से कैसे मिलना चाहिए।

अभिनेत्री ने आगे कहा, जब मैं कैरेक्टर के नर्स वाले हिस्से की तैयारी कर रही थीं, तो हमें ऑपरेशन थिएटर और हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल फॉलो करने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। हमें वह ट्रेनिंग शूट से पहले मिली थी, इसलिए मेकर्स ने सब कुछ संभाल लिया था।

अभिनेत्री ने बताया कि वह एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो कई सालों से खेलों में अपना योगदान देते आए हैं। उन्होंने कहा, मैं एक स्पोर्ट्स फैमिली से ताल्लुक रखती हूं। मेरे दादाजी हॉकी खेलते थे और फिटनेस मेरे खून में है। इसलिए आर्मी स्टांस रखना और जरूरी बॉडी पोस्चर बनाए रखना मेरे लिए थोड़ा आसान था। साथ ही, एक प्रोफेशनल डांसर होने से भी मुझे मदद मिली।

अशिमता बख्शी ने शो के बारे में बताया, यह शो श्रीनगर के असल आर्मी हॉस्पिटल से प्रेरित है, लेकिन शूट वहां नहीं हुआ। हमने मुंबई स्टूडियो में शूट किया और इसका कुछ हिस्सा कश्मीर में शूट किया गया। शो असल अनुभवों से प्रेरित है। किरदार काल्पनिक हैं, लेकिन कहानियां असल हॉस्पिटल के अनुभवों से प्रेरित हैं।

स्वकर के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन

श्रीनगर गढ़वाल (आरएनएस। स्वकर के विरोध में व्यापारियों ने नगर निगम परिसर से लेकर बोर्ड बैठक तक विरोध दर्ज कराया। गणेश बाजार से जुलूस निकालकर नगर निगम पहुंचे व्यापारियों ने पहले सभागार के बाहर सांकेतिक धरना दिया। इसके बाद सभागार में पहुंचकर चल रही बोर्ड बैठक के बीच भी प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने स्वकर वापस लेने की मांग उठाते हुए मेयर आरती भंडारी को ज्ञापन सौंपा।व्यापार सभा के पदाधिकारी और अन्य व्यापारी व्यापार एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नगर निगम पहुंचे। निगम सभागार में इस दौरान बोर्ड बैठक चल रही थी। सभागार के दरवाजे बंद होने पर व्यापारी बाहर सांकेतिक धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। दरवाजे खुलने पर व्यापारी सभागार में पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए बोर्ड के समक्ष स्वकर का मुद्दा उठाया। व्यापारियों ने कहा कि श्रीनगर को नगर निगम बनाए जाने के बाद उन पर अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। सरकार या तो स्वकर माफ करे अथवा इसे वापस लेकर पूर्व नगर पालिका की व्यवस्था के अनुरूप कर निर्धारण करे। उन्होंने कहा कि पहले से ही व्यापार चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नए कर और शुल्क से कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। प्रदर्शन में व्यापार सभा अध्यक्ष अनुज जोशी, महासचिव छवि प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पंकज नेगी, व्यापार जिला अध्यक्ष वासुदेव कंडारी, प्रवीण अग्रवाल, रामानंद भट्ट, शार्दुल शाह, जावेद अंजूम, आसिफ, खिलेंद्र चौधरी और आशीष सडाना आदि शामिल रहे।

टिहरी झील क्षेत्र को जल्द मिलेगा स्मार्ट पर्यटन का नया स्वरूप : डीएम

नई टिहरी(आरएनएस। टिहरी झील और आसपास के क्षेत्रों में एडीबी से सहायतित विकास योजनाएं और पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने के लिए प्रस्तावित स्मार्ट कंपोनेंट और स्मार्ट लूप को लेकर डीएम नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में पर्यटन रोड की प्रगति, रोड पर प्रस्तावित कार्य, शहर और मुख्य मोटर मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्मार्ट पोल, स्मार्ट बस शेल्टर, व्यू प्वाइंट, आईसीसीसी भवन और ई-बस सेवा सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। स्मार्ट बस शेल्टर में यात्रियों के बैठने, प्रकाश व्यवस्था, डिजिटल सूचना डिस्प्ले, सीसीटीवी और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं। स्मार्ट पोल में प्रकाश व्यवस्था के साथ सीसीटीवी और सूचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना भी है। टिहरी झील के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए व्यू प्वाइंट को आकर्षक बनाने पर जोर दिया गया। डीएम ने कहा कि ई-बस सेवा का लाभ अधिक से अधिक स्थानीय लोगों और पर्यटकों को मिल सके, इसके लिए रूट का निर्धारण प्रमुख पर्यटन स्थलों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करें। बैठक में पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत, एसएसपी श्वेता चौबे और एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी आदि मौजूद थे।

सू- दोकू क्र.076

	2			6			1	
3			4			2		
							6	
6					4			
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.75 का हल

8	7	6	9	5	1	2	3	4
1	3	9	2	8	4	5	6	7
4	5	2	3	7	6	9	1	8
2	8	5	4	6	7	1	9	3
3	1	7	8	9	2	4	5	6
6	9	4	1	3	5	7	8	2
9	4	1	6	2	8	3	7	5
7	2	8	5	1	3	6	4	9
5	6	3	7	4	9	8	2	1

श्रीनगर गढ़वाल में 26 दिन खराब रही हवा, चिंता बढ़ाने वाले हैं वायु गुणवत्ता के आंकड़े

श्रीनगर गढ़वाल(आरएनएस। हिमालय की गोद में बसे श्रीनगर की हवा को लेकर सामने आए एक साल के आंकड़े तस्वीर का दूसरा पहलू दिखा रहे हैं। प्रदूषण के महीन कणों के साथ ओजोन का बढ़ा स्तर भी शहर की वायु गुणवत्ता के लिए चिंता का कारण बना है। हिमालयी क्षेत्र की हवा को साफ-सुथरी मानने की धारणा के बीच श्रीनगर की वायु गुणवत्ता के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि की हिमालयी वातावरणीय एवं अंतरिक्ष भौतिकी शोध प्रयोगशाला के एक साल के अध्ययन में पीएम-2.5 और पीएम-1०(वायु में मौजूद बहुत छोटे और ठोस कण व तरल बूंदें) प्रमुख प्रदूषक पाए गए। वहीं 26 दिनों में ओजोन का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक रहा।

15 सितंबर 2०25 से 15 सितंबर 2०26 तक के 339 वैध दिनों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर मंगलवार को भौतिकी विभाग, चौरास परिसर में पांचवां ग्रीनहाउस गैस एवं वायु गुणवत्ता सूचना बुलेटिन जारी किया गया। अध्ययन के अनुसार पीएम-2.5 की औसत सांद्रता 73.3० माइक्रोग्राम और पीएम-1० की 1००.48 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। पीएम-2.5 की मात्रा 169 दिन और पीएम-1० की मात्रा 146 दिन निर्धारित 24 घंटे की सीमा से अधिक रही।

सबसे चौंकाने वाली स्थिति 19 दिसंबर 2०25 को सामने आई, जब ओजोन का आठ घंटे का औसत 634.13 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया। इसी दिन प्रति घंटे ओजोन की सांद्रता 88० माइक्रोग्राम से अधिक दर्ज की गई। वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दियों में घाटी में प्रदूषकों के फंसने, स्थानीय स्तर पर बायोमास जलाने और मौसमीय परिस्थितियों से इस घटना का संबंध हो सकता है।

भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. त्रिलोक चंद्र उपाध्याय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ समाज तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने डॉ. गौतम और उनकी शोध टीम अमनदीप विश्वकर्मा, अंकित कुमार और सरस्वती रावतको जनहितकारी वैज्ञानिक पहल के लिए बधाई दी।

मौसम के अनुसार प्रदूषण के स्तर में देखा गया बदलाव

हिमालयी वातावरणीय एवं अंतरिक्ष भौतिकी शोध प्रयोगशाला के अन्वेषक डॉ. आलोक सागर गौतम ने कहा कि अध्ययन में मौसम के अनुसार प्रदूषण के स्तर में बदलाव भी सामने आया। सर्दियों में तापमान प्रतिलोमन के कारण पीएम बढ़ा, जबकि गर्मियों में अधिक तापमान और सौर विकिरण से ओजोन का स्तर बढ़ा। मानसून में बारिश के कारण पीएम अपेक्षाकृत कम रहा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी 22 दिन निर्धारित सीमा से अधिक दर्ज हुआ। कहा कि धरातल के पास अधिक मात्रा में मौजूद ओजोन हानिकारक वायु प्रदूषक है।

बीडीसी की बैठक में छाये रहे राशन कार्ड और बिजली के मुद्दे

काशीपुर(आरएनएस)। क्षेत्र पंचायत विकास समिति (बीडीसी) की बैठक में राशन कार्ड और बिजली संबंधी समस्याओं के मुद्दे छाए रहे। इस दौरान विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें राशन कार्ड, श्रम विभाग में पारदर्शिता, बिजली लाइनों की मरम्मत और बिजली आपूर्ति सुचारु रखने के लिए शटडाउन का रोस्टर समय से जारी करने का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा प्राधिकरण के कार्यों, नहरों के रखरखाव तथा जल संस्थान और जल निगम के कार्यों की भी समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों ने अपने विभागों की संचालित योजनाओं की जानकारी दी और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पात्र लोगों को चिह्नित करने को कहा।बैठक में परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, ज्येष्ठ उप प्रमुख तरसेम सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष जसपाल सिंह जस्सी, बीडीओ कमल किशोर पांडे, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य समेत 98 जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मांडई संकुल ने जीती कबड्डी, नाली संकुल खो-खो में रहा अव्वल

कोटद्वार(आरएनएस। राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही दुगड्डा ब्लॉक के बेसिक स्कूलों की दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हो गया। कबड्डी में मांडई संकुल ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। वहीं खो-खो प्रतियोगिता में नाली संकुल अव्वल रहा।

प्राथमिक बालिका वर्ग की 5० मीटर दौड़ में ललिता, अंशिका और मीनाक्षी ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। 1०० मीटर में ललिता और गीतिका ने स्थान हासिल किए। 2०० मीटर में रालमा, अंशिका रावत और आराध्या, 4०० मीटर में आराध्या, अंशिका रावत और पलक क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहीं। लंबी कूद में ललिता, अंशिका और आरती ने शीर्ष तीन स्थान प्राप्त किए। सब जूनियर बालिका वर्ग की 2०० मीटर दौड़ में वैष्णवी रावत, युक्ता बिष्ट और अंकिता, 4०० मीटर में मानवी, वैष्णवी रावत और सुहानी बिष्ट, 6०० मीटर में सुहानी बिष्ट, जेनम और सृष्टि ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। उच्च प्राथमिक बालक वर्ग की ऊंची कूद में अक्षत, नैतिक और समर तथा लंबी कूद में मनन, अनुज और नाजिम ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। बैडमिंटन में राधिका रावत, सौम्य नेगी और स्मृति क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। खो-खो में नाली संकुल विजेता और मांडई संकुल उपविजेता रहा।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुमन कोटनाला और पार्षद जयप्रकाश ध्यानी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर ब्लॉक खेल समन्वयक अरुण कुकरेती, सह समन्वयक एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लक्ष्मी नैथानी, गोपाल जसोला, प्रकाश चौधरी, कुलगौरव द्विवेदी, सुबोध ध्यानी, राजेंद्र पाल, विजय पाल, सुरेश सिंह और वीरेंद्र भंडारी आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता का संचालन व्यायाम शिक्षक सुरदीप गुसाईं और भोपाल सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया।

किसाऊ बांध के विरोध में बच्चों संग सड़क पर उतरे ग्रामीण

विकासनगर (आरएनएस। किशाऊ बांध परियोजना के विरोध में क्वानू क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों के साथ सड़क पर उतर आए। हाथों में तख्तियां लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बांध निर्माण के फैसले का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि परियोजना आगे बढ़ी तो कई गांवों के अस्तित्व पर संकट आएगा और सिंचित कृषि भूमि जलमग्न हो सकती है। इससे खेती पर निर्भर परिवारों के सामने रोजगार और रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।

प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कहा कि उनके लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि पीढ़ियों से जुड़ी जन्मभूमि, आजीविका और सामाजिक पहचान है। बांध बनने से गांवों से विस्थापन हुआ तो बच्चों को भी अपने पुश्तैनी गांव, खेत, स्कूल और सामाजिक परिवेश से दूर होना पड़ेगा।

ग्रामीणों ने कहा कि बच्चों को प्रदर्शन में साथ लाने का उद्देश्य यह बताना है कि परियोजना का असर केवल वर्तमान पीढ़ी पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध निर्माण का निर्णय लेने से पहले प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त रूप से विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि परियोजना से होने वाले संभावित लाभों की चर्चा की जा रही है, लेकिन डूब क्षेत्र, कृषि भूमि, मकानों, जंगल, स्थानीय रोजगार और विस्थापन के सामाजिक प्रभाव को लेकर ग्रामीणों की चिंताओं का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है।

ग्रामीणों ने सरकार से मांग की कि परियोजना को लेकर प्रभावित गांवों में खुली जनसुनवाई कराई जाए और प्रत्येक गांव पर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाए। उन्होंने जमीन के मुआवजे के साथ-साथ आजीविका, पुनर्वास, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक पुनर्वास की ठोस योजना पहले सार्वजनिक करने की मांग की। कहा कि विकास परियोजनाओं का विरोध विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी परियोजना की कीमत यदि स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, घर और जड़ों से विस्थापित होकर चुकानी पड़े तो सरकार को उनके सवालों का जवाब देना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ग्रामीणों की चिंताओं का समाधान किए बिना परियोजना को आगे बढ़ाया गया तो विरोध को और व्यापक किया जाएगा।

दिल्ली एनसीपी कार्यालय में सौरभ आहूजा ने की राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंट

हमारे संवाददाता

नई दिल्ली/देहरादून। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के उत्तराखंड राज्य कॉर्डिनेटर सौरभ आहूजा ने आज नई दिल्ली स्थित एनसीपी कार्यालय में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा से सप्रेम भेंट की।

भेंट के दौरान आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की तैयारियों तथा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस संबंध में सौरभ आहूजा को आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हुए। बैठक में उत्तराखंड में संगठन के विस्तार, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। सौरभ आहूजा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा का मार्गदर्शन एवं विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया।

कोल पावर प्लांट पर घिरी धामी..

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

की कुल वित्तीय देनदारी क्या होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस पूरी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता के सभी मानकों का पालन हुआ? सरकार इन सवालों का तथ्यात्मक जवाब देकर विवाद को खत्म कर सकती है।

वहीं कांग्रेस के लिए भी आरोपों से आगे बढ़कर दस्तावेजों और ठोस तथ्यों के साथ अपने सवालों को साबित करना चुनौती होगी। बिजली की जरूरत उत्तराखंड की है, भुगतान भी उत्तराखंड के उपभोक्ताओं को करना है। इसलिए चुनावी शोर से अलग इस करार की असली कसौटी यही होगी कि 25 साल की यह व्यवस्था राज्य को कितनी सुनिश्चित, किफायती और विश्वसनीय बिजली देती है।

सेवा संकल्प के बहाने भाजपा की..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

शक्ति केंद्र स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसलिए आने वाला एक महीना भाजपा के लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनसंपर्क की क्षमता और स्थानीय नेतृत्व की पकड़ परखने का अवसर भी है। जहां संगठन मजबूत है, वहां अभियान आसानी से जमीन पकड़ सकता है, जहां स्थानीय स्तर पर असंतोष या निष्क्रियता है, वहां वही अभियान पार्टी के लिए फीडबैक का माध्यम बन सकता है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भाजपा ने सेवा को अपने जनसंपर्क अभियान का केंद्रीय शब्द बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने से इसे जोड़ा गया है और उत्तराखंड में अभियान को विकसित भारत 2०47 के संकल्प से जोड़ने की बात कही गई है। लेकिन चुनावी राजनीति में किसी अभियान की वास्तविक प्रभावशीलता नारों से नहीं, जनता की प्रतिक्रिया से तय होती है। सेवा संकल्प अभियान के दौरान भाजपा के सामने यही सबसे महत्वपूर्ण फीडबैक होगा कि सरकार की उपलब्धियों का संदेश कितनी दूर तक पहुंचा और जमीन पर जनता किन सवालों को प्राथमिकता दे रही है।

कुल मिलाकर, चुनावी साल में भाजपा का सेवा संकल्प अभियान सरकार के कामकाज का प्रचार अभियान होने के साथ-साथ संगठन के लिए जनता की नब्ज टटोलने का अवसर भी है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस जनसंपर्क से केवल अपनी उपलब्धियों की सूची तैयार करती है या जनता की शिकायतों और अपेक्षाओं को भी चुनावी रणनीति में जगह देती है। 2०27 की राजनीतिक लड़ाई में यही फीडबैक आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सैन्य बहुल राज्य का सियासी गणित...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

के अवसरों को स्पष्ट रूप से रखे। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह अपने आरोपों को ठोस आंकड़ों और अग्निवीरों की वास्तविक स्थिति से जोड़कर जनता के सामने रखे। 2०27 की चुनावी राजनीति में अग्निवीर योजना पर बहस आगे और तेज हो सकती है। भाजपा इसे युवा शक्ति, राष्ट्र सेवा और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ सकती है, जबकि कांग्रेस इसे स्थायी रोजगार और युवाओं के भविष्य के सवाल के रूप में उठाएगी।

इस राजनीतिक टकराव में 54 लाख आवेदनों का आंकड़ा भाजपा के लिए बड़ा प्रचार बिंदु है, लेकिन चुनावी विमर्श में इससे आगे भी सवाल खड़े होंगेकृचार साल बाद अग्निवीरों का करियर कैसा रहा, कितनों को स्थायी रोजगार मिला और पुनर्वास की व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित हुई? यानी अग्निवीर पर चुनावी सियासत में फिलहाल दो नैरेटिव आमने-सामने हैं। भाजपा का युवाओं का उत्साह और अवसर बनाम कांग्रेस का भविष्य की सुरक्षा और स्थायी रोजगार। आने वाले चुनावी महीनों में इन दोनों दावों की असली परीक्षा युवाओं के बीच होने वाली राजनीतिक बहस और उपलब्ध आंकड़ों से होगी।

उत्तराखण्ड के 100 प्रमुख ट्रेक एवं हाइक रूट्स की होगी जीपीएस/जीआईसी मैपिंग

संवाददाता

JAI MAA BHAGWATI
GPS MAPPING & TECH
SURVEY OF 100 TRE
UTTARAKHAI
UK07PA6843

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से उत्तराखण्ड के 100 प्रमुख ट्रेक एवं हाइक रूट्स की जीपीएस/जीआईसी मैपिंग एवं तकनीकी सर्वेक्षण के लिए जाने वाले अभियान दल को फ्लैग ऑफ किया। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा गठित टीमें चयनित ट्रेक रूट्स का स्थलीय सर्वेक्षण कर उनकी विस्तृत जीपीएस/जीआईसी मैपिंग करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में साहसिक एवं ट्रेकिंग पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के प्रसिद्ध ट्रेकिंग क्षेत्रों के साथ ही दूरस्थ एवं कम प्रसिद्ध ट्रेक रूट्स को सुव्यवस्थित रूप से पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस पहल से ट्रेकिंग को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ पर्यटकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रेक रूट्स की वैज्ञानिक मैपिंग से ट्रेकर्स को मार्ग से संबंधित आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के साथ उत्तराखण्ड की संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए गाइडिंग, होमस्टे एवं पर्यटन से जुड़ी अन्य गतिविधियों के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल ने जानकारी दी कि परियोजना के तहत राज्य के 100 प्रमुख ट्रेक एवं हाइक रूट्स की जीपीएस/जीआईसी मैपिंग तथा तकनीकी सर्वेक्षण किया जाएगा। मैपिंग के आधार पर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन जीपीएस नेविगेशन ऐप विकसित किया जाएगा, जिससे नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने की स्थिति में भी ट्रेकर्स अपने मोबाइल फोन पर ट्रेल एवं रूट से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि परियोजना के सफल क्रियान्वयन के बाद उत्तराखण्ड सभी 100 मैप किए गए ट्रेक मार्गों को कवर करने वाला ऑफलाइन एवं ऑनलाइन जीपीएस नेविगेशन ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। ऐप ट्रेकर्स को बेहतर नेविगेशन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ आपातकालीन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी उपयोगी होगा। सचिव पर्यटन ने बताया कि मैपिंग के दौरान ट्रेक रूट्स पर कैंप साइट्स, डस्टबिन एवं शौचालय के लिए उपयुक्त स्थानों की भी पहचान की जाएगी। इससे भविष्य में ट्रेकिंग रूट्स पर आवश्यक सुविधाओं के विकास, बेहतर कूड़ा प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा सकेगा। उत्तराखण्ड पर्यटन के आधिकारिक मास्टर प्लान में भी ट्रेक मार्गों की सुरक्षा, संचार सुविधा, संकेतक और आपातकालीन निकासी जैसी व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य में सतत एवं विज्ञान आधारित पर्यटन मॉडल विकसित करने में सहायक होगी। परियोजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और कॉफी टेबल बुक भी तैयार की जाएगी, जिससे राज्य के कम प्रसिद्ध ट्रेकिंग क्षेत्रों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, अपर सचिव पर्यटन एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अभिषेक रुहेला, अपर निदेशक पर्यटन श्रीमती पूनम चंद एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

◆मुख्यमंत्री ने जीपीएस/जीआईसी मैपिंग एवं तकनीकी सर्वेक्षण के लिए अभियान दल को किया फ्लैग ऑफ

शिव-शक्ति की भव्य प्रस्तुति ने मोहा श्रद्धालुओं का मन

संवाददाता

देहरादून। छठे गणेश महोत्सव के दूसरे दिन शिव-शक्ति की भव्य प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।

72 सीढ़ी आस्था पथ स्थित गंगेश्वर घाट माँ गंगा आरती समिति की ओर से छठे गणेश महोत्सव के अवसर पर आशीर्वाद वाटिका में आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक संध्या श्रद्धा, संस्कृति और कला के अद्भुत संगम की साक्षी बनी। दिल्ली से पहुंचे बॉलीवुड टी-सीरीज फ्रेम सुप्रसिद्ध कलाकार नितिन चक्रधारी एवं उनकी पूरी टीम ने 'रुद्र राग' और 'महाकाल की लीला' की भव्य एवं भावपूर्ण प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक भाव से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर नितिन चक्रधारी ने भगवान शिव, जबकि सोनिया ने शक्ति के स्वरूप की भूमिका निभाई। शिव और शक्ति के दिव्य स्वरूप में कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुति, मंचीय कला और प्रभावशाली अभिनय ने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने धार्मिक कथाओं को मनोरंजन के साथ-साथ आध्यात्मिक अनुभूति से भी जोड़ दिया।

भव्य प्रस्तुति के उपरांत गंगेश्वर घाट माँ गंगा आरती समिति की ओर से नितिन चक्रधारी एवं उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। वहीं, शीशम झाड़ी स्थित श्री माँ कात्यायनी मंदिर में भी नितिन चक्रधारी एवं उनकी टीम का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मंदिर के संस्थापक-संचालक गुरविंदर सलूजा ने कलाकारों का स्वागत करते हुए उनकी प्रस्तुति की सराहना की। इस अवसर पर मयंक चक्रवर्ती एवं परिवार, सोनू चक्रवर्ती, न्यू स्टार क्लब के संस्थापक के.के. सचदेवा एवं परिवार, सान्या सचदेव छाबड़ा, न्यू स्टार क्लब अध्यक्ष मनोज साहल, अजय ब्रेजा एवं परिवार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

मंदिर के संस्थापक गुरविंदर सलूजा ने कहा कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और पौराणिक कथाओं को मंचीय कला के माध्यम से नई पीढ़ी और जन-जन तक पहुंचाना भी है। कार्यक्रम में 'रुद्र राग' और 'महाकाल की लीला' के माध्यम से श्रद्धा, संस्कृति और कला का ऐसा सुंदर संगम देखने को मिला, जिसने उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ी।

तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, दो युवकों की मौत

हमारे संवाददाता

नैनीताल। सड़क हादसे मे देर रात एक तेज रफ्तार बाइक के सड़क के किनारे पेड़ से टकरा जाने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।

मामला हल्द्वानी-रामपुर मार्ग पर टांडा पुलिस चौकी के पास का है। यहां देर रात तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार चेतन चौहान, निवासी फुलशुंगी, रुद्रपुर और वैभव छाबरा, निवासी नंद विहार कॉलोनी, फुलशुंगी, रुद्रपुर की मौत हो गई। दोनों मृतकों की पहचान होने के बाद उनके परिजन अस्पताल पहुंच गए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार, हादसा देर रात टांडा पुलिस चौकी के पास हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक तेज गति में थी। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों युवक सड़क किनारे झाड़ियों में पड़े रहे। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लिया।

शुरुआती दौर में मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन पुलिस की जांच के बाद दोनों की पहचान हुई। मृतकों की पहचान की सूचना मिलने के बाद दोनों के परिजन अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है।

चौकी प्रभारी के अनुसार, पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई है। दुर्घटना से जुड़े साक्ष्यों को भी जांच के लिए सुरक्षित किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक तेज गति के कारण अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हालांकि हादसा वास्तव में किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बाइक की स्थिति, घटनास्थल और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय बाइक की गति कितनी थी और दुर्घटना से ठीक पहले घटनास्थल पर क्या परिस्थितियां थीं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है।

पंजाब में एएसआई की गोली मारकर हत्या

अमृतसर (संवाददाता)। अमृतसर में एएसआई हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें गोली तब मारी गई जब वह ड्यूटी से लौट रहे थे।

गेट हकीमा पुलिस स्टेशन में तैनात हरजीत सिंह की ड्यूटी पेट्रोलिंग में थी। बीती रात हरजीत सिंह ड्यूटी खत्म करके घर की तरफ जा रहे थे तभी भगतावाला दाना मंडी के गेट नंबर दो के बाहर अज्ञात लोगों ने हरजीत की गर्दन में गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अस्पताल में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान ने ली है। हालांकि पंजाब पुलिस ने आतंकी हमले के एंगल का खंडन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिखा, अमृतसर जिले में अपनी ड्यूटी निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर हरजीत सिंह की बहादुरी को दिल से सलाम, उनकी असीम हिम्मत और कर्तव्य के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब सरकार दुख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, पंजाब सरकार की ओर से परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि और एचडीएफसी बैंक की ओर से 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बीमा भुगतान दिया जाएगा। हम अपने शहीदों और उनके परिवारों को हरसंभव मदद देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उनका सर्वोच्च बलिदान हम सभी को पूरी बहादुरी और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।

अंकिता भण्डारी हत्याकांड की चौथी बरसी पर विभिन्न संगठनों ने दिया धरना

संवाददाता

देहरादून। अंकिता भण्डारी हत्याकांड की चौथी बरसी पर अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सदस्य गांधी पार्क में एकत्रित हुए जहां पर उन्होंने धरना दिया और अंकिता भण्डारी को श्रद्धांजलि देते हुए न्याय की मांग की। उनका कहना था कि मामले की सीबीआई मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए। उत्तराखण्ड बार कौंसिल की पूर्व चेयरपर्सन रजिया बेग ने कि आधा अधूरा न्याय न्याय नहीं होता है। उनका कहना था कि सरकार मुख्य अपराधी को छुपा रही है। जब वीआईपी की बात सामने आयी है तो सरकार को पता लगाना चाहिए कि वह वीआईपी कौन था जिसके चलते अंकिता भण्डारी की हत्या की गयी। सीबीआई ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी जांच कहां तक पहुंची है।

महिला मंच की कमला पंत का कहना था कि वीआईपी जेल में नहीं गये यह सरकार का नकारापन साबित होता है। उनका कहना था कि अभी तक सीबीआई यह नहीं पता लगा सकी की रिजार्ट में बुलडोजर किसने चलाया तथा साक्ष्य मिटाने का काम किसने किया और किसके इशारे पर किया। इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए। उनका कहना था कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता संघर्ष जारी रहेगा।

प्रशांत भूषण ने रिटायमेंट के बाद कई पूर्व सीवीसी चीफ, कैग चीफ के रिलायंस ज्वाइन करने पर उठाए सवाल

संवाददाता

नई दिल्ली। जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सेवानिवृत्ति के बाद निजी कंपनियों में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी नौकरियों पर रोक नहीं होनी चाहिए, जिनसे पद पर रहते हुए हितों के टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।

प्रशांत भूषण ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि पूर्व सीवीसी और कैग प्रमुखों, बैंकों व सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों तथा सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने सेवानिवृत्ति के बाद रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान नियामक या महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए रिलायंस से जुड़े मामलों को भी देखा था।

उन्होंने अपनी पोस्ट में एसबीआई की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, पूर्व सीवीसी केवी चौधरी, बीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन सार्थक बेहुरिया, इंडियन ऑयल के पूर्व चेयरमैन संजीव सिंह और गेल के पूर्व महानिदेशक प्रभात सिंह समेत कई अधिकारियों के नाम गिनाए।

सूची में जीआईसी की पूर्व चेयरमैन डी. सेनगुप्ता, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन एवं एमडी केके पुरवार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कृष्ण मुरारी, पूर्व कैग राजीव महर्षि, पूर्व वित्त सचिव आरएस गुजराल, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एमके जैन और आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व प्रमुख केवी कामथ के नाम भी शामिल हैं।

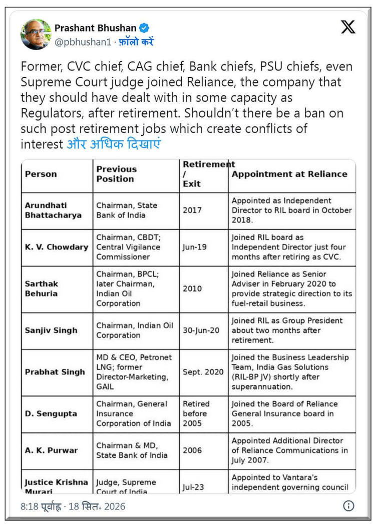

Prashant Bhushan
@pbhushan1 · फ़ॉलो करें

Former, CVC chief, CAG chief, Bank chiefs, PSU chiefs, even Supreme Court judge joined Reliance, the company that they should have dealt with in some capacity as Regulators, after retirement. Shouldn't there be a ban on such post retirement jobs which create conflicts of interest और अधिक दिखाएं

Person	Previous Position	Retirement / Exit	Appointment at Reliance
Arundhati Bhattacharya	Chairman, State Bank of India	2017	Appointed as Independent Director to RIL board in October 2018.
K. V. Chowdary	Chairman, CBDT; Central Vigilance Commissioner	Jun-19	Joined RIL board as Independent Director just four months after retiring as CVC.
Sarthak Behuria	Chairman, BPCL; later Chairman, Indian Oil Corporation	2010	Joined Reliance as Senior Adviser in February 2020 to provide strategic direction to its fuel-retail business.
Sanjiv Singh	Chairman, Indian Oil Corporation	30-Jun-20	Joined RIL as Group President about two months after retirement.
Prabhat Singh	MD & CEO, Petronet LNG; former Director-Marketing, GAIL	Sept. 2020	Joined the Business Leadership Team, India Gas Solutions (RIL-BP JV) shortly after superannuation.
D. Sengupta	Chairman, General Insurance Corporation of India	Retired before 2005	Joined the Board of Reliance General Insurance board in 2005.
A. K. Purwar	Chairman & MD, State Bank of India	2006	Appointed Additional Director of Reliance Communications in July 2007.
Justice Krishna Murari	Judge, Supreme Court of India	Jul-23	Appointed to Vantara's independent governing council

8:18 पूर्वाह्न · 18 सित. 2026

1320 मेगावाट थर्मल पावर करार उत्तराखंड के हित में है या निजी कंपनी के: बिष्ट

संवाददाता

देहरादून। यूकेडी के केन्द्रीय महामंत्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट ने कहा कि 1320 मेगावाट थर्मल पावर करार उत्तराखण्ड के हित में है या निजी कम्पनी के हित में है।

आज यहां उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने धामी सरकार के अदाणी पावर से 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली 25 वर्षों तक 5.746 प्रति यूनिट की दर से खरीदने के फैसले को अर्थहीन करार दिया। राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि यदि 1320 मेगावाट बिजली को 25 वर्षो तक लगातार 24 घंटे की क्षमता के आधार पर गणना करें तो इसकी कीमत लगभग 1.66 लाख करोड़ बैठती है। यानी उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं पर यह बेहद बड़ा दीर्घकालीन वित्तीय कर्ज होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2024 में यूजेवीएनएल और टीएचडीसी के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट विकसित करने की पहल हुई थी, तो उस सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवस्था को क्यों समाप्त किया गया? इसके बाद यूपीसीएल ने नया टेंडर निकाला और अब यह करार अदाणी पावर के साथ हुआ है। 1320 एमडब्लू परियोजना उत्तराखंड में लगाने के बजाय छत्तीसगढ़ में क्यों? छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड तक बिजली लाने का ट्रांसमिशन और अन्य अतिरिक्त खर्च कौन वहन करेगा? 25 वर्षों में बिजली की वास्तविक कुल लागत कितनी होगी? यूजेवीएनएल-टीएचडीसी के संयुक्त उपक्रम को समाप्त करने से उत्तराखंड ने क्या खोया? यदि परियोजना उत्तराखंड के सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विकसित होती तो स्थानीय रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण, निम कार्य प्रणाली को प्रकट करता है, सरकार तत्काल मूल और संशोधित टेंडर दस्तावेज सार्वजनिक करे। क्या इन बदलावों से परियोजना की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई? इसकी स्वतंत्र जांच हो। 5.746 प्रति यूनिट की दर में फिक्स्ड चार्ज, ऊर्जा शुल्क, ट्रांसमिशन तथा अन्य लागतों का वास्तविक विभाजन क्या है? बिष्ट ने कहा कि हमारे जल, जंगल और जमीन से जुड़े संसाधनों के बावजूद यदि सरकार 25 वर्षों के लिए इतनी बड़ी राशि निजी कंपनी को बिजली खरीद में देने जा रही है, तो जनता को पूरे सौदे का हिसाब जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत करने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के बजाय यदि सरकार लगातार सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम करके निजी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ाएगी, तो यह उत्तराखंड के दीर्घकालीन हितों के लिए गंभीर प्रश्न है। उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता है कि 1320 एमडब्लू करार से संबंधित पूरा टेंडर, सभी बदली गई शर्तें, पावस सप्लाई एग्रीमेंट टैरिफ की गणना, ट्रांसमिशन लागत और 25 वर्षों की अनुमानित कुल वित्तीय देनदारी सार्वजनिक की जाए तथा पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार
समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट
कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।